लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 1 - 15 अप्रैल 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक - 63

"सार्थक दिशा में किया गया अभ्यास, कर्म की उत्कृष्ट सफलता की कुंजी है।

: आलोक

घसोला पशु प्रदर्शनी में पहुंचे हजारों पशुपालक

4

अखिल भारतीय वन खेल-कूद प्रतियोगिता

7

संस्कृति का प्राण है लोक साहित्य

8

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़संकल्प

विशेष प्रतिनिधि

किसी भी परिवार की आजीविका के लिए जरूरी है रोज़गार। गुजर-बसर करने के लिए बुनियादी जरूरतें तथा अन्य जरूरतें इसी रोजगार के जरिए मयस्सर होती हैं। रोज़गार यानी काम-धाम न हो तो रसोई का न्यूनतम खर्च भी भारी लगने लगता है। पौने तीन करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में कोई परिवार अभाव में न जीए, इस ओर वर्तमान राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। सबके विकास की संकल्पबद्ध नीति पर चलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के तमाम परिवारों को रोज़गार मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है। राज्य सरकार न केवल युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा रही है, अन्य अति गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 'परिवार पहचान-पत्र' डाटा से गरीब परिवारों तथा बेरोज़गार युवाओं की वास्तविक संख्या मिल रही है जिनके आधार पर तेज़ी से कार्य किया जा रहा है।

शिक्षित युवा, बेरोज़गार न रहें इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका युवाओं को खूब फ़ायदा मिल रहा है। योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं तथा कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें कामगार भी बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि काबिलियत के आधार पर नौकरियां दिए जाने का सिलसिला शुरू होने के बाद प्रदेश का शैक्षणिक माहौल बदला है। पढ़ाई-लिखाई के प्रति उदासीन हो गए युवाओं में नए उत्साह का संचार देखा जा रहा है। युवा अब 'पर्ची-खर्ची' की बजाय परीक्षा के सलेबस की चर्चा करते हैं।

विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय स्तर पर तकनीकी व औद्योगिक शिक्षा देने के विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। रोज़गार विभाग द्वारा राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों तथा सरकार में अस्थायी कार्य आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए 'सक्षम युवा प्लेसमेंट सैल' और 'हरियाणा रोज़गार पोर्टल' विकसित किए गए हैं। रोज़गार मेले के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र व विदेश में रोज़गार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

राज्य सरकार की योजना ग्रुप सी व ग्रुप डी में वर्ष 2023- 24 में 65,000 से अधिक पदों पर नियमित भर्ती करने की है। इन पदों को भरने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा की मदद भी ली जाएगी। इनके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1,636 करोड़ रुपए आंवटित किए गए हैं।

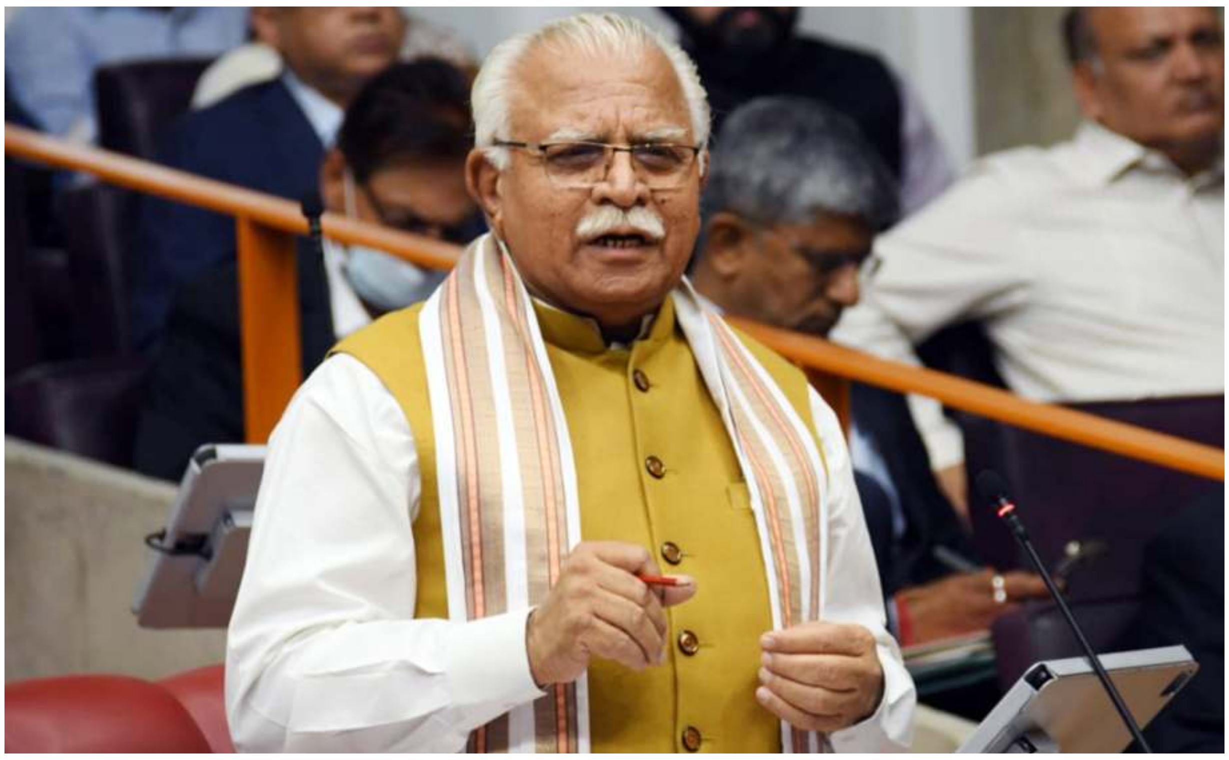

> वर्तमान सरकार ने आठ साल में एक लाख 994 नौकरियां दी हैं। इनके अलावा सक्षम युवा योजना के तहत विद्यार्थियों को 100 घंटे काम के बदले क्रमशः 3,000, 1,500 तथा 900 रुपए मासिक दिये जाते हैं। अब तक इस योजना का 1.75 लाख युवाओं ने लाभ उठाया है। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण देकर एक लाख से अधिक युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। वर्ष 2015 के बाद निजी क्षेत्र में भी 12.64 लाख युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाया गया है।
>
> -मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

बेरोज़गारी दर घटी

राज्य के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाने की पहल के अंतर्गत प्रदेश में बेरोज़गारी की दर पहले से घटी है। वर्तमान में फरवरी 2023 में रोज़गार कार्यालय में दर्ज आवेदकों की संख्या 6.46 लाख है, जबकि दिसंबर 2014 में यह संख्या 7.86 लाख थी। समय-समय पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सर्वे करवाया जाता है। पीएलएफएस की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2017-18 में बेरोज़गारी दर 8.6 प्रतिशत, घटने बढ़ने के बाद यह दर फरवरी 2023 में 6.46 फीसदी पहुंच गई है।

विदेशों में रोज़गार

हरियाणवी युवाओं के लिए रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने विदेश सहयोग विभाग, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग में हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल को सक्रिय किया है। 'हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सैल' विदेशों में प्लेसमेंट की आवश्यकताओं और कौशल की ज़रूरतों की पहचान करेगा और विदेशों में इन नौकरियों के लिए हरियाणा के युवाओं को प्रशिक्षित करेगा।

अनुबंध पर नौकरी:

हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड सरकारी क्षेत्र में अनुबंध पर कर्मियों की भर्ती के लिए प्राथमिक स्रोत बन गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रोल पर 1. 06 लाख से अधिक कर्मी हैं। निगम द्वारा परिभाषित मानदंडों के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति की जाती है। जिसका प्राथमिक मापदंड न्यूनतम योग्यता का आधार और पात्र आवेदक के परिवार की आय की स्थिति है। वर्ष 2023-24 में रोज़गार निगम प्राइवेट सेक्टर में कर्मियों की नियुक्ति के लिए युवाओं की पहचान, कौशल प्रशिक्षण तथा उनकी नियुक्ति संबंधी सेवाओं की पेशकश करेगा।

कौशल शिक्षा

हरियाणा सरकार ने कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा से समेकित कर शैक्षणिक स्तर 2023-24 से कक्षा छठी से आठवीं तक में भी कौशल शिक्षा देने की योजना बनाई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने में तीन लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की छात्राओं को 2500 रुपए की मदद का प्रस्ताव किया गया है।

G20 भारत 2023 INDIA

विधेयक पारित

हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र में कुल पांच विधेयक पारित हुए। हरियाणा विनियोग विधेयक, 2023 व हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 विधेयक दूसरे सत्र में पारित हुए। इससे पूर्व वाले सत्र में जो विधेयक पारित हुए उनमें पंडित लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023 व हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 और हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल हैं।

बजट सत्र के लिए विधानसभा की कुल आठ बैठकें हुई। सभी विधायकों ने अपने अपने हलके की समस्याओं व मांगों के साथ सुझाव रखे। बजट से पूर्व भी सभी विधायकों व हितधारकों से सुझाव मांगे गए थे। करीब 700 सुझावों में से 68 को बजट में शामिल किया गया।

प्राकृतिक खेती अपनाएं किसान

चरखी दादरी गुरुकुल में प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज़ागरूक करने के लिए प्राकृतिक कृषि कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिमाचल व गुजरात की तर्ज़ पर हरियाणा में भी प्राकृतिक खेती करने पर अधिक ज़ोर दिया। कार्यशाला में राज्यपाल ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने का संकल्प दिलवाया। राज्यपाल देवव्रत ने किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीक सिखाने के लिए चरखी दादरी में प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की और इस पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने सहमति दे दी। आर्य हिंदी संस्कृत महाविद्यालय में स्वामी ओमानंद स्मृति दिवस समारोह एवं प्राकृतिक कृषि कार्यशाला में दादरी, भिवानी, लोहारू, तोशाम, बहल, सिवानी आदि के सैंकड़ों किसानों ने शिरकत की।

प्राकृतिक खेती से ज़मीन होगी उपजाऊ

राज्यपाल आचार्य देवव्रत आर्य ने कहा कि प्राकृतिक खेती के दम पर ही देश की भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी बात सुनकर बजट में प्राकृतिक खेती का प्रावधान कर दिया है। रासायनिक खेती की वज़ह से हमारा खान-पान पूरी तरह से विषैला हो चुका है और ज़मीन बंजर होती जा रही है। आम नागरिक कैंसर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग आदि भयानक बिमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले किसानों को हर संभव मदद की जाएगी। इससे किसानों का उपज भी अच्छा होगा और लोगों का खान-पान भी बेहतर होगा।

प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण केंद्र

जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग से शाखा बना दी है, जो कि किसानों को पेस्टीसाइड यूरिया के स्थान पर गोबर से बनाई गई खाद का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गाय की खरीद पर 25 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। कृषि मंत्री ने आर्य महाविद्यालय संस्थान के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। दादरी के विधायक सोमबीर सांगवान ने आर्य हिंदी संस्कृत महाविद्यालय के लिए 11 लाख रुपए देने का घोषणा की।

- संवाद ब्यूरो

संपादकीय

बजट-सत्र के 45 घंटे

इस बार बजट-सत्र के 45 घंटों में विकास व जागरुकता की एक अनूठी इबारत लिखी गई। विधानसभा सत्र की समाप्ति पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा की कुल 8 बैठकें हुई और 45 घंटे तक सभी विधायकों ने अपने-अपने हलके की समस्याओं, मांगों, सुझावों को रखा। इससे पहले बजट से पूर्व विधायकों व अन्य हितधारकों से मुख्यमंत्री ने सुझाव मांगे थे। उन्होंने बताया कि 700 सुझावों में से 68 सुझावों को बजट में शामिल किया गया। अब पहली अप्रैल से नये वित्त वर्ष की शुरुआत होगी और बजट में घोषित नई योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्तमान सरकार का यह नौवां बजट है और जिसमें से चार बजट स्वयं उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 का बजट सब बजटों पर भारी पड़ता है और यह हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल सरकार द्वारा बिजली उत्पादन के लिए पानी के गैर-खपत उपयोग के लिए जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर (वॉटर सेस) लगाने के अध्यादेश का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह वॉटर सेस, अवैध है और हरियाणा राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। इसलिए इसे हिमाचल सरकार द्वारा तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। हरियाणा विस बजट-सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार के इस अध्यादेश का विरोध करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जिसका विपक्ष ने भी समर्थन दिया और प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ।

सदन ने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि वह हिमाचल प्रदेश सरकार को यह अध्यादेश वापिस लेने के लिए आदेश दे, क्योंकि यह केंद्रीय अधिनियम यानी अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 का भी उल्लंघन है। मनोहर लाल ने प्रस्ताव पढ़ते हुए बताया कि इस वॉटर सेस से भागीदार राज्यों पर प्रति वर्ष 1,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा जिसमें से लगभग 336 करोड़ रुपए का बोझ हरियाणा राज्य पर पड़ेगा। यह सेस न केवल प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के विशेष अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन की लागत भी अधिक होगी।

-डा. चंद्र त्रिखा

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना

सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और अग्रणी कदम उठाते हुए अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दयालु योजना का शुभारंभ किया है।

दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर एक लाख 80 हजार रुपए तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाएगा।

बता दें प्रदेश में चल रही मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है।

न्यास द्वारा तीन योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रुप सी व डी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना, छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना तथा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शामिल है।

ऑनलाइन मिलेगी सहायता राशि

दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता के मामले में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को और स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डाटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा।

योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल होगी। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लाभार्थियों, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए तक है, उनका प्रीमियम हरियाणा सरकार दे रही है।

- संवाद ब्यूरो

ट्राईसिटी में मैट्रो की तैयारी

केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ ट्राईसिटी यानि चंडीगढ़, मोहाली व पंचकूला में परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए मैट्रो की तैयारी शुरू की है। इस बारे में चंडीगढ़ सचिवालय में पंजाब के गवर्नर बीएल पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल, पंजाब की पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान और चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता उपस्थित हुए।

बैठक में राइट्स कंपनी के अधिकारियों की ओर से पूरे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दी गई। इसके बाद हरियाणा व पंजाब की ओर से सुझाव रखे गए।

मैट्रो प्रोजेक्ट का उद्देश्य तीनों शहरों में यातायात को बेहतर बनाना है। पूरे प्रोजेक्ट पर अनुमानित खर्च 10570 करोड़ रुपए है। मैट्रो पर सबसे अधिक 7680 करोड़ खर्च होंगे। इसमें से मोहाली में 4080, चंडीगढ़ में 2320 और पंचकूला में 1280 करोड़ रुपए खर्च आएगा। सहमति बनी तो इस प्लान को अंतिम मुहर के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। जिसके बाद प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू होगा।

हरियाणा की ओर से सुझावः मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मैट्रो के माध्यम से पिंजौर-कालका को चंडीगढ़ से जोड़ने का सुझाव दिया। मैट्रो के विस्तार में घग्गर नदी और नए पंचकूला के क्षेत्रों को शामिल किए जाने की बात भी कही। उन्होंने पंजाब के जीरकपुर को पिंजौर-कालका तक जोड़ने का सुझाव दिया, ताकि लोगों को चंडीगढ़ आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके।

हरियाणा सिविल सचिवालय, विधानसभा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, पीजीआई चंडीगढ़ और एयरपोर्ट के मैट्रो से जुड़ने पर ट्रैफिक जाम मुक्ति मिलेगी।

सलाहकार संपादक :	डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक :	मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर :	संगीता शर्मा
संपादन सहायक :	सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन :	गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट :	विकास डांगी

फसल नुकसान की भरपाई कर रही सरकार

ओलावृष्टि और बारिश के कारण हुए नुकसान की सरकार भरपाई कराएगी। गिरदावरी के जरिए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। किसानों से लगातार अपील की गई है कि वे पोर्टल पर अवश्य जानकारी देते रहें।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि साल 2022 में ओलावृष्टि से फसल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए 151.42 करोड़ रुपए तथा 2021 में भारी वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 614. 63 करोड़ रुपए और 2020 में खरीफ फसल के नुकसान के लिए 269.77 करोड़ रुपए और रबी फसल के लिए 114.44 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं । इस प्रकार पिछले 2 साल में 1150.26 करोड़ रुपए किसानों को देने का कार्य किया है जो की यूपीए सरकार के 10 साल के बराबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी 5657.02 करोड़ रुपए खरीफ 2016 से रबी 2021-22 तक का पैसा अलग से किसानों के खाते में भेजा गया है।

राज्य सरकार सूखे, धूल भरी आंधी, भूकंप, आग शार्ट-सर्किट या बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, आसमानी बिजली, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, शीत लहर, पाला, लू तथा कीट हमलों से हुए फसल क्षति, पशुपालन नुकसान, मत्स्य नुकसान, हस्तशिल्प, हथकरघा नुकसान, आवास के लिए पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करती है।

33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल का नुकसान होने पर 75 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर 15000 रुपए प्रति एकड़, 75 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 12000 रुपए प्रति एकड़ और 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 9000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा हर हिस्सेदार को न्यूनतम 500 रुपए बोये गये क्षेत्र तथा अधिकतम 5 एकड़ प्रति किसान सीमा के अधीन सहायता राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत के बीच फसलों में हुए नुकसान के लिए पूर्ण मुआवज़ा राशि राज्य सरकार के बजट से वहन की जाती है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 26 अक्तूबर, 2014 से 28 फरवरी 2023 तक पिछले आठ साल के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, भारी वर्षा, जलभराव, आग, ओलावृष्टि, कीट हमले और शीत लहर, पाला से फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को लगभग 3902.43 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की गई है। रबी फसल 2023 की खराबा रिपोर्ट अभी तक अपेक्षित है।

-संवाद ब्यूरो

शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता के मुताबिक यमुनानगर-जगाधरी के पास हमीदा हैड की भूमि पर पड़े ठोस कचरे को प्लांट तक पहुंचाने का कार्य 31 मार्च, 2023 तक पूरा हो जाएगा।

प्रगति का आधार 'छोटी सरकार'

ग्राम पंचायतों की बढ़ी ताकत, विकास कार्यों में निभाएंगी अहम भूमिका

मनोज प्रभाकर

देश की आत्मा गांव में निवास करती है। गांव खुशहाल होंगे तो देश स्वस्थ एवं संपन्नता की राह पर होगा। लोगों का जीवन सहज व सरल होगा। महात्मा गांधी के इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए देश में आजादी के बाद निरंतर प्रयास हुए हैं। मगर उक्त प्रयासों की निष्ठा एवं गति पर राजनीतिक स्तर पर वैचारिक भेद रहा है। बहुतों का मानना है कि गांव का विकास उम्मीदों के अनुरूप नहीं हुआ। वजहें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही हो या प्रशासनिक कमजोरी, मगर यह आरोप बराबर टिका रहा कि ग्राम विकास के लिए प्रति वर्ष तय होने वाला बजट अपनी 'टेल' तक नहीं पहुंच पाया। कुल मायने, व्यवस्था में कहीं न कहीं खामी रही।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आजादी के अमृतकाल में इन खामियों को दूर करने का दृढ़ संकल्प लिया है। वे एक कुशल इंजीनियर की तरह ठोक-पीटकर व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भविष्य में भी कोई परेशानी न हो।

ग्रामीण विकास को शुचितापूर्ण ढंग से गति देने के लिए प्रदेश में पढ़ी-लिखी पंचायतों का चयन कराया गया है। पिछले कार्यकाल में पढ़ी-लिखी पंचायतों का चयन हुआ था जिसका परिणाम ग्रामीण विकास में खूब दिखाई दिया। युवा प्रतिनिधियों ने पूरे उत्साह से विकास कार्य कराए। कंधा से कंधा मिलाकर चले तथा गैर सरकारी संस्थाओं से भी सहयोग लेने में कामयाब रहे।

दूसरी बार चुनकर आई पंचायतों को सशक्त करने का प्रयास किया गया है। पंचायतों के अधिकारों का विस्तार किया गया है ताकी जनप्रतिनिधि खुली सोच के साथ विकास कार्य करा सकें। कार्यों में पारदर्शिता रहे इसके लिए ई टेंडरिंग नीति लागू की गई है।

उक्त नीति के तहत न केवल विकास कार्यों को गति मिलेगी बल्कि बजट का सही इस्तेमाल हो सकेगा। नए प्रावधानों के मुताबिक ग्राम सरपंच अपने स्तर पर यानी कोटेशन के आधार पर गांव में पांच लाख रुपए तक के कार्य करा सकेंगे। इससे अधिक की राशि के कार्यों के लिए उच्च तकनीकी अधिकारियों की स्वीकृति अनिवार्य रहेगी। उनके लिए संबंधित कार्यालय कार्य करने वाले ठेकेदार अथवा एजेंसियों से ऑनलाइन बोली आमंत्रित करेंगे। इस प्रक्रिया से काम तेज़ी से होंगे।

गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी तय की गई हैं। बड़ी पंचायतों के लिए कुछ अलग मानक तय किए गए हैं। पांच लाख रुपए तक कार्यों की गुणवत्ता की जिम्मेवारी सरपंचों की होगी तथा उससे अधिक के कार्यों में कमी पाई गई तो अधिकारी नपेंगे।

> राज्य सरकार का सपना गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित करना है। सरकार 9 सूत्रीय कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रही है। गांवों में जिम, लाइब्रेरी, महिला संस्कृति केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा, कूड़ा प्रबंधन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट और अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
>
> **-देवेंद्र बबली, पंचायत मंत्री, हरियाणा**

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों की मांग पर उनका मानदेय तीन हजार से बढ़ाकर 5000 रुपए तथा पंचों का मानदेय एक हजार से बढ़ाकर 1600 रुपए किया है। यह मानदेय एक अप्रैल 2023 से मान्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, सरपंचों को ग्राम सचिव की गोपनीय रिपोर्ट पर टिप्पणी करने का अधिकार भी दिया है।

पंचायती प्रतिनिधियों से कहा गया है कि इस वित्त वर्ष के आखिरी तिमाही के लिए आवंटित किए गए 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव अपलोड कर दें। ग्राम पंचायतों को 800 करोड़, ब्लॉक समितियों को 165 करोड़ तथा जिला परिषदों को 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मार्च के पहले पखवाड़े तक 6217 पंचायतों में से 5048 पंचायतों ने विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित कर दिए गए।

गुणवत्ता की जांच के लिए कमेटी

विकास कार्यों की सोशल-ऑडिट के लिए ग्राम स्तर पर मौजिज लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो गांव में होने वाले विकास कार्यों पर नजर रखेगी। विकास एवं पंचायत विभाग के लिए अलग से इंजीनियरिंग विंग गठित की जाएगी। विकास कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए 6 माह में सोशल ऑडिट सिस्टम स्थापित होगा तथा इसके लिए 'गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण' की स्थापना भी की जा रही है।

> ग्राम सरपंच जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेवारी समझें और गांव के विकास कार्य पारदर्शिता से करवाएं। ई-टेंडरिंग नीति में कोई कठिनाई नहीं आएगी, आएगी तो उसे दूर किया जाएगा। सरकार ने ई-टेंडरिंग से सरपंचों के हाथ मजबूत करने का काम किया है, इससे न केवल विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी, कार्य शीघ्रता से पूरे होंगे।
>
> **-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री**

पंचायतों को आर्थिक मदद

बिजली के बिलों पर लगाया जा रहा पंचायत कर बकाया राशि सहित एक अप्रैल से पंचायतों को दे दिया जाएगा। इसमें से पंचायतों के लंबित बिजली बिल की कटौती करके हर तिमाही में भुगतान किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की राशि ग्राम पंचायत को दी जाएगी।

जिला परिषदों की जिम्मेवारी बढ़ी: खेत-खलिहानों के चार करम से कम चौड़े रास्ते जिला परिषदों के माध्यम से पक्के करवाए जाएंगे। जिला परिषद को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सड़कों की मरम्मत का कार्य सौंपा जाएगा। इसके अलावा, स्वच्छता अभियान के तहत गांवों में घर-घर से कुड़ा उठवा कर निस्तारण करने, स्ट्रीट लाइट, मिड-डे मिल, बस क्यू शैल्टर जैसे कार्य भी दिए जाएंगे।

जवाबदेही की व्यवस्था

शिकायतों की सुनवाई समय पर नहीं हुई तो नपेंगे अधिकारी

प्रदेश में नागरिकों को तय समय सीमा में सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) बेहद कारगर साबित हो रहा है। इस सिस्टम के लागू होने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने से सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव आया है और आमजन को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उनके काम निर्धारित समय-सीमा के अंदर होने लगे हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया तो उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अब उन्हें किसी भी सरकारी सेवा लेने के लिए दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। 'आस' शुरू होने से काम पारदर्शिता के साथ होने लगे हैं और वहीं अधिकारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित होने से तय समय सीमा में ही लोगों को सेवाएं मिल रही हैं।

प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदेही तय करने, जनता को सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने, कागजी कार्य को कम से कम करने और लिटिगेशन कम करने के लिए राज्य सरकार ने 1 सितंबर, 2021 को 'ऑटो अपील सिस्टम' की शुरुआत की थी। इस सिस्टम पर 33 विभागों की 384 सेवाएं ऑनबोर्ड की जा चुकी हैं। आस के लागू होने से समय पर सेवा न मिलने पर नागरिक की ओर से प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी को एक स्वचालित अपील की जाती है। यदि

प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी 30 कार्य दिवसों के भीतर अपील का निपटान नहीं करता है, तो अपील स्वचालित रूप से द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के पास चली जाती है। इसी तरह, यदि वह भी 30 कार्य दिवसों के भीतर अपील का निपटान नहीं करता है, तो अपील स्वचालित रूप से सेवा का अधिकार आयोग के पास जाती है। सेवा का अधिकार आयोग के द्वारा ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। 'आस' के अंतर्गत 5 सितंबर, 2021 से 17 मार्च, 2023 तक कुल 6,54,799 अपील दायर हो चुकी हैं। इनमें से 6,10,145 अपीलों का निपटान किया जा चुका है।

मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार नागरिकों को अपील मुक्त व्यवस्था प्रदान करने की ओर अग्रसर है ताकि लोगों को तय समय अवधि में ही सारी सेवाएं मिल जाए,

> सरकार ने देरी से सेवाएं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट करने के लिए 'आस' को कारगर ढंग से लागू किया है। यदि निर्धारित अवधि में सेवा न मिले तो फाइल रोकने वाले पर कार्रवाई तय है। पहले सेवा का अधिकार आयोग के पास बहुत कम शिकायतें आती थीं, अब समय पर काम न होने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत सेवा का अधिकार आयोग के पास खुद-ब-खुद चली जाती है। कुछ अधिकारियों द्वारा सेवा देने में हुई देरी के कारण जुर्माना भी लगाया है।
>
> **-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा**

उन्हें किसी भी स्तर पर अपील करने की आवश्यकता ही न पड़े। इसी तरह राजस्व विभाग में पहले कई स्तर तक अपील करनी पड़ती थी, जिसमें कई साल गुजर जाते थे। इसके समाधान के लिए भी प्रदेश सरकार ने रिमांड प्रथा को खत्म किया और केवल दो स्तर तक ही अपील का प्रावधान किया। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है।

भूटान देश हैपिनेस इंडेक्स के माध्यम से अपने नागरिकों के सुखमय जीवन को मापता है। हरियाणा सरकार भी ईज ऑफ लिविंग की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि प्रदेशवासियों का जीवन भी खुशहाल व समृद्ध बने। अपील अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन या सरल हेल्पलाइन 0172-3968400 पर कॉल करके भी दायर की जा सकती है।

अंबाला में राजीव गांधी खेल परिसर में चार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। इस बारे में कोई और मांग सामने आती है तो उस पर भी विचार किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कैथल शहर के अंबाला रोड से तितरम मोड़ जींद रोड़ तक एनएच द्वारा बाईपास बना दिया गया है और बाहर जाने वाले सभी वाहन इस बाईपास से गुजर रहे हैं।

मुर्राह नस्ल का रहा बोलबाला

घसोला पशु प्रदर्शनी में पहुंचे हजारों पशुपालक

- » मुर्राह नस्ल के संरक्षण एवं विकास के लिए सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- » मुर्राह भैंसों के मालिकों को 30,000 रुपए तक का नकद प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- » राज्य में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के क्षेत्र में सरकार द्वारा सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं।
- » प्रदेश सरकार पशुओं के संरक्षण के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य के प्रति भी सजग है।
- » राज्य में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 11.20 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है।
- » सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत आठ करोड़ 19 लाख पशुओं का बीमा किया गया है।
- » राज्य के पशुपालकों को एक करोड़ तैंतालीस लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और पशुपालकों को एक हजार करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
- » राज्य में 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान' योजना के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग को सबसे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 22 हजार 482 पशु डेयरी यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें से 10 हजार 592 लाभार्थियों को सबसिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

गांवों का सम्पूर्ण विकास पशुपालन की प्रगति के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। राज्य में अधिकतर पशुधन लघु एवं सीमांत किसान तथा कृषि मजदूर द्वारा ही पाला जाता है। इस तथ्य को वर्तमान सरकार ने भली-भांति पहचान कर अपने कार्यकाल के आरंभ से ही पशुपालन संबंधी योजनाओं को नया रूप दिया है तथा इन्हें कारगर ढंग से लागू किया है।

इसी पहल में आजादी अमृत महोत्सव की शृंखला में दादरी शहर से सटे घसोला मार्ग पर 11-13 मार्च तक 39वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में भले ही मुर्राह नस्ल के झोटों और शानदार घोड़ों का दबदबा रहा, मगर इन सबके बीच हरियाणा नस्ल की देसी गायों की भी खूब धूम दिखाई दी। मेले में उत्तम किस्म के पशु देखने को मिले और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के वैज्ञानिकों ने लोगों को पशुधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।

बजट में बढ़ोतरी

पशुधन प्रदर्शनी-2023 के समापन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पशुओं की देखभाल हेतु प्रदेश में छह पॉलीक्लीनिक बनाये जाएंगे। चरखी दादरी में भी एक पॉलीक्लीनिक बनाया जाएगा। वर्तमान में सात पॉलीक्लीनिक कार्यरत हैं। इसके अलावा, प्रदेश में गौ वंश की देखभाल के लिए गौ सेवा आयोग के बजट में 10 गुणा बढ़ोत्तरी करके 400 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने पशुधन प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान' योजना के तहत जिन परिवारों की आय एक लाख रुपए से कम है, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अधिकतर परिवार पशुपालन के काम में आगे आ रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए बैंकों के माध्यम से इन परिवारों को ऋण दिलवाया जा रहा है। इस साल दो लाख परिवारों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पशुपालन या अन्य किसी कार्य के लिए इन दो लाख परिवारों के लिए 2,000 करोड़ रुपए रिजर्व रखा गया है।

सांझी डेयरी

वर्ष 2023-24 के बजट में एक नया प्रोजेक्ट सांझी डेयरी की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के तहत पंचायत की ज़मीन पर एक शेड बनाया जाएगा, जिसमें पशुपालक, जिनके पास अपने पशु बांधने के लिए जगह नहीं है, वे इस कॉमन शेड में अपने पशुओं को रख सकेंगे। सहकारिता विभाग द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। अप्रैल, 2023 से इस योजना को लॉन्च किया जाएगा।

गौ वंश की सुरक्षा के लिए कड़े कानून

प्रदेश सरकार ने गौ वंश की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए हैं। गौ हत्या करने पर दस साल तक की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया है। हरियाणा में 632 गौशालाएं है। गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है। बेसहारा गौ वंश की देखभाल के लिए बजट में वृद्धि की गई है। इसमें उन गौशालाओं को अधिक बजट दिया जाएगा, जो बेसहारा गौ वंश की देखभाल करेंगी। पंचायत या अन्य संस्थाएं भी गौशाला बनाकर पशुओं की देखभाल करेंगी, उन्हें भी अनुदान दिया जाएगा।

कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हरियाणा अकेला प्रदेश है, जहां आठ लाख से ज़्यादा पशुओं का बीमा किया गया है। भारत सरकार की नीतियों के अनुसार प्रदेश में एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा, जहां पशुपालक कॉल करके एंबुलेंस की मांग कर सकेंगे। उसके बाद तुरंत नजदीकी एंबुलेंस पशुपालक के घर जाएगी। पहले चरण में 70 एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। बाद में 200 एंबुलेंस होंगी।

पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने प्रदेश के पशुपालकों से आह्वान किया कि वे हरियाणा को प्रति पशु दूध उत्पादन में इजराइल के बराबर ले जाने का संकल्प लें। उन्होंने बताया कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के वैज्ञानिकों ने सरोगेटरी तकनीक से बछड़िया पैदा करने में सफलता हासिल की है। इसी प्रकार भैंस अनुसंधान द्वारा क्लोन से झोटा पैदा करने में भी सफलता हासिल की है। इससे निश्चित रूप से प्रदेश दूध उत्पादन में आगे बढ़ेगा।

- संगीता शर्मा

पशुओं के साथ हिंसक व्यवहार नहीं: राज्यपाल

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि पशुओं के साथ कदापि हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। पशुओं के साथ सदैव प्रेमवत रवैया अपनाएं, उनमें भी इंसान की तरह मानवीय संवेदनाएं होती हैं। राज्यपाल ने प्रदर्शनी में गौ माता को गुड़ खिलाकर उसका सम्मान किया और ऊंट, घोड़े, बकरी, मेंढे आदि के करतब देखे। उन्होंने कहा कि पशुपालकों के अथक परिश्रम की बदौलत हरियाणा का वार्षिक दुग्ध उत्पादन 116 करोड़ 29 लाख टन पर पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति 108 3 ग्राम दुग्ध उपलब्धता के साथ देश में पंजाब के बाद हरियाणा दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति प्रति दिन दुग्ध उपलब्धता 427 ग्राम की है।

पानी बचाने के लिए खेती में बदलाव जरूरी

राज्य सरकार मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए हरी खाद (ढैंचा) को भी बढ़ावा दे रही है और किसानों को ढैंचा बीज पर 80 प्रतिशत सब्सिडी पर प्रदान की जाएगी। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे गर्मियों की फसलों मुख्य रूप से मूंग, सब्जियां के तहत क्षेत्र और उपज बढ़ाने में मदद मिली है। पानी की कमी को कम करने के लिए लेजर लैंड लेवलिंग तकनीक और पाइप के माध्यम से जल वितरण प्रणाली का उपयोग करने से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि होगी।

गर्मी के दौरान एक लाख एकड़ में ग्रीष्मकालीन मूंग को बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी पर बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। कृषक उत्पादक संगठन की भागीदारी के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण क्षमता और मूल्यवर्धन में सुधार किया जाएगा ताकि किसानों को कीमतों में गिरावट की स्थिति में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। राज्य ने पहले ही 731 एफपीओ स्थापित कर लिए हैं।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार धान की सीधी बिजाई को भी बढ़ावा दे रही है। डीएसआर तकनीक से करीब 30 फीसदी पानी की बचत होती है। डीएसआर तकनीक अपनाने के लिए किसानों को 72000 एकड़ जमीन पर डीएसआर अपनाने के लिए 4000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 38 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। आगामी सीजन के दौरान राज्य सरकार ने 80 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डीएसआर के तहत 2 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा है।

-संवाद ब्यूरो

कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि पंचकूला में गांव रत्तेवाली के पास पुल के निर्माण के डिजाइन में संशोधन के बाद खर्च बढ़कर 609.24 लाख रुपए हुआ है। कार्य एक जून 2023 तक शुरू होने की संभावना है

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय भूजल बोर्ड, उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंडीगढ़, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा की भू-जल प्रकोष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से 31 मार्च, 2022 तक तैयार की गई क्षमता रिपोर्ट जारी की।

हरियाणा संवाद
पाक्षिक : 1 - 15 अप्रैल 2023

कृषि मेला

अत्याधुनिक तकनीक एवं जानकारी से लाभान्वित हुए किसान

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 2023-2024 के बजट अभिभाषण में गांवों को समृद्ध बनाने पर फोकस किया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में 10-12 मार्च, 2023 तक हरियाणा कृषि विकास मेला का आयोजन किया गया जहां हरियाणा के ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों के किसानों ने भी अपनी हाज़िरी दर्ज़ कराई और मेले के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के चलते फसल चक्र में आ रहे बदलाव पर विकसित की जा रही फसलों की नई-नई किस्मों व तकनीक की जानकारी दी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1966 हरियाणा गठन के बाद शायद यह पहला अवसर था जब एक साथ कृषि एवं पशु मेलों का आयोजन प्रदेश में हुआ है। कृषि विश्वविद्यालय व पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से लोगों ने ग्रामीण समृद्धता के बारे में जानकारियां ली हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज समय की ज़रूरत है कि हम सब एक नई कृषि क्रांति की शुरुआत करें। इस कार्य में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय व शोध संस्थाओं के वैज्ञानिक मिलकर शोध कार्यों के लिए सहयोग करें और नई विधाओं को आगे लेकर आएं। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे खेती में जहां कृषि लागत कम होगी, वहीं अच्छी उपज होने के साथ-साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कृषि उपकरणों व उत्पादों से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अंडरग्राउंड पाईपलाइन पोर्टल तथा ई-रूपी ऐप भी लॉन्च किए।

निर्यात करें फल सब्जीः मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नये-नये प्रयोग किए जा रहे हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से कार्गो फ्लाइट शुरू करने की पहल की जाएगी, ताकि हरियाणा के किसानों की ताज़ा फल एवं सब्ज़ियां अरब देशों को निर्यात की जा सके। मुख्यमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे कम लागत और अधिक पैदावार कैसे हो, इस विषय पर शोध करें और उन्नत किस्म के बीज तैयार करें। साथ ही खाद्यानों की मार्केटिंग के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो, यह कार्य मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किया जाए।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा : मनोहर लाल ने कहा कि आज केमिकल व कीटनाशकों के अत्याधिक प्रयोग से खाद्यानों की गुणवत्ता प्रभावित हो गई है, इस पर ध्यान देने ज़रूरत है। इसके लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की सब्सिडी दे रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि लगातार पानी के दोहन से भूमिगत जल नीचे जा रहा है। पानी की कमी के चलते किसान नगदी फसलों को अपनाएं, जिनमें फल, फूल, सब्ज़ी के साथ-साथ मधुमक्खी पालन, पशुपालन तथा मत्स्य पालन आदि शामिल हैं।

मनोहर लाल ने कहा कि पहली बार प्रदेश में हमारी सरकार ने राजस्थान की सीमा के साथ लगते 300 टेलों, जहां पिछले 25 साल से पानी नहीं पहुंचा था, वहां भी पानी पहुंचाया है। जो प्रगतिशील किसान अन्य किसानों को प्रगतिशील बनाने में सहयोग करेंगे, उन किसानों को सरकार की ओर से ईनाम दिए जाएंगे।

कृषि को बढ़ावा देती योजनाएं

- सूक्ष्म सिंचाई के लिए सरकार किसानों को 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है।
- बरसाती पानी को वापिस जमीन में डालने के लिए बोरवेल लगाए जा रहे हैं।
- डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी व अन्य आर्थिक मदद किसानों के खाते में भेजी जा रही है।
- लगभग 52 हजार करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे गए। पारदर्शिता से सरकार को 1,200 करोड़ रुपए की बचत हुई।
- प्रदेश की 80 लाख एकड़ खेती योग्य भूमि का विवरण तैयार किया जा रहा है।
- किसान अपनी फसल का पूरा विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं।
- किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए एफपीओ गठित किए जा रहे हैं।
- हरियाणा पहला प्रदेश है, जो 11 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है।
- 'भावांतर भरपाई योजना' के तहत किसानों को एमएसपी और खरीद मूल्य के अंतर को भी किसानों को दिया रहा है।
- 'मेरा पानी मेरी विरासत योजना' के तहत अन्य फसलें उगाने पर किसानों को 7 हजार रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- 'फसल बीमा योजना' के तहत लगभग 6,000 करोड़ रुपए किसानों को मिला है।

- संवाद ब्यूरो

सब्र की खेती चंदन

संगीता शर्मा

चंदन व अंजीर की खेती में किसानों ने अपना भाग्य आजमाना शुरू कर दिया है। चंदन के पेड़ों के साथ-साथ मौसमी सब्ज़ियों की खेती करके किसान मुनाफ़ा कमा रहे हैं। ऐसा ही उदाहरण फतेहाबाद के खाराखेड़ी गांव के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र कुमार बिश्नोई है, जिनकी चंदन की खेती रंग दिखाने लग गई है। इसके साथ ही किसानों को प्रेरित करके 100 एकड़ में अंजीर की खेती के लिए प्रेरित किया है। सुरेंद्र कुमार को हरियाणा सरकार की ओर से हाल ही में आयोजित किसान मेले के दौरान प्रगतिशील किसान के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।

सुरेंद्र कुमार ने वर्ष 2017 में दो एकड़ ज़मीन में चंदन की खेती शुरू की थी और अब इसकी लंबाई 18-20 फीट हो गई है। दस वर्ष में ये पेड़ पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार होंगे और कटाई करके चंदन के पेड़ से प्रति एकड़ करोड़ों का मुनाफ़ा लिया जा सकता है। चंदन की खेती के लिए प्रति एकड़ करीब 4 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। सुरेंद्र ने बताया कि चंदन के यह पौधे कर्नाटक के मैसूर से हिमाचल लाए गए थे और दोस्त महावीर हुड्डा का आइडिया था और कृषि विभाग से रिटायर्ड एसडीओ डॉ. रामपाल सांगवान की मदद से खेत में चंदन की खेती शुरू की। एक पौधे का खर्चा एक हजार रुपए रहा है। एक एकड़ में 320 पौधे रोपित किये है।

सुरेंद्र ने बताया कि आरंभ में चंदन की खेती के साथ-साथ चने व पपीते की खेती थी और मुनाफ़ा भी कमाया। दो एकड़ में चंदन व एक एकड़ में अंजीर व अन्य गेहूं, सरसों, कॉटन की खेती करते हैं। चंदन के पेड़ के बीच-बीच में छोटी फसल की मौसमी सब्ज़ियां उगाते हैं। ये घर के ज़रूरत के हिसाब से उगाते हैं। उन्होंने बताया कि चंदन की जैविक खेती कर रहे हैं। देसी गाय की खाद, जीवामृत व अन्य जैविक उपायों का प्रयोग खेती में करते हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग के सहयोग से 'न्यू नैना देवी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' का गठन किया है।

उन्होंने बताया कि सफेद चंदन की खेती कर रहे हैं और अब देखते हैं कि भविष्य में कितनी दमदार लकड़ी निकलती है। वह कहते है कि मैसूर की सफेद चंदन में सात प्रतिशत तेल की मात्रा है और हरियाण के मौसम के हिसाब से लकड़ी में पांच से छह प्रतिशत तेल होने की उम्मीद है। चंदन के पेड़ की कटाई जितनी अधिक देर से की जाए उतनी ही लकड़ी अच्छी व कीमत अधिक मिलती है।

चंदन की व्यवसायिक खेती

एक बार चंदन का पेड़ आठ साल का हो जाता है, तो उसका हर्टवुड बनना शुरू हो जाता है और रोपण के 12 से 15 साल बाद कटाई के लिए तैयार हो जाता है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो किसान हर साल 15-20 किलो लकड़ी आसानी से काट सकता है। यह लकड़ी बाज़ार में करीब तीन-सात हजार रुपए प्रति किलो बिकती है। कभी-कभी इसकी कीमतें 10,000 रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच जाती है। चंदन की खेती के लिए हमें ऐसी जलवायु का चुनाव करना चाहिये जो की गर्म और शुष्क हो। चंदन के पौधों को अधिक 35 डिग्री तथा न्यूनतम 15 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके पौधे अधिक धूप को आसानी से सहन कर सकते है।

उपयुक्त भूमि का चयन

चंदन की खेती दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। पर इसे लाल मिट्टी और अन्य जगहों पर भी कर सकते हैं, पर रेतीली मिट्टी में आप इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हर तीन से चार महीने में वर्मी कंपोस्ट और केचुंआ खाद डालते रहना चाहिए।

दीर्घकालिक मुनाफ़ा

सफेद चंदन की खेती से किसान धैर्य रखकर दीर्घकालिक मुनाफ़ा ले सकता है। चंदन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम है। इसमें एंटी बायोटिक तत्व है जो कि सिर दर्द, घाव भरने, खुजली दूर करने तनाव दूर करने और दात दर्द में राहत देता है और स्किन संबंधी रोगों में चंदन एक बहु उपयोगी औषधि की तरह है। सफ़ेद चंदन की लकड़ी अधिक खुशबू वाली होती है, जिस वज़ह से इसकी कीमत लाल चंदन की अपेक्षा अधिक होती है। इसे साबुन, इत्र, चंदन तेल और सौंदर्य प्रसाधनों जैसी महंगी चीजों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

भूगर्भ जल संसाधन आकलन के अनुसार भूजल के विकास के स्तर में सुधार हुआ है। वर्ष 2020 के दौरान प्रदेश में औसतन भू-जल दोहन का स्तर 134.56 प्रतिशत था, जो 2022 के दौरान 134.14 प्रतिशत तक पहुंच गया।

दक्षिणी क्षेत्र बिजली से संबंधित शिकायत के लिए मुख्य अभियंता के कार्यालय में 01662-223302 पर संपर्क कर सकता है या ई मेल से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

छोटे व्यापारियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना

जिन व्यापारियों का टर्नओवर 20 लाख रुपए सालाना है, उन्हें जीएसटी पंजीकरण के लिए अब सीए प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से निःशुल्क प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने यह घोषणा हरियाणा निवास में आयोजित व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का शुभारंभ करते हुए की।

मनोहर लाल ने कहा कि छोटे व्यापारियों को अपना पंजीकरण कराने के लिए सीए प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है और इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है। अब इस घोषणा के बाद छोटे व्यापारी, जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है, वे सरकार द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए प्रमाणपत्र ले सकेंगे। इस खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में व्यापारियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का दायरा बढ़ाकर अब इस योजना में छोटे व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को भी शामिल किया गया है।

यह योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार मुआवज़ा राशि प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत उन व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा, जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को या बाद की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं। ऐसे करदाता योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होने चाहिए। उनके पंजीकरण शुल्क का भुगतान हितधारक अर्थात हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा 'हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास' को किया गया होना चाहिए। इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपए तक के कारोबार पर 20 लाख रुपए तक मुआवज़ा राशि दी जाएगी। मुआवजा राशि और पंजीकरण शुल्क का विवरण इस प्रकार है -

श्रेणी	मुआवजा कवरेज	वार्षिक पंजीकरण शुल्क
0 से 20 लाख रुपए तक	5 लाख रुपए तक	100 रुपए
20 से 50 लाख रुपए तक	10 लाख रुपए तक	500 रुपए
50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक	15 लाख रुपए तक	1,000 रुपए
1 से 1.5 करोड़ रुपए तक	20 लाख रुपए तक	2,500 रुपए

जीएसटी संग्रह के मामले में हरियाणा शीर्ष पर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह के मामले में 68142 करोड़ की कलेक्शन के साथ हरियाणा बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे आम आदमी और सरकार के बीच सेतु होते हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हरियाणा के व्यापारियों का राज्य के जीएसटी संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान है।

मनोहर लाल ने कहा कि कोई भी व्यापारी जब भी अपनी दुकान बंद कर घर वापस पहुंचता है तो उसे किसी भी कारण से अनहोनी की आशंका रहती है। इसलिए ऐसे सभी व्यापारियों के व्यवसाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार जल्द ही रेहड़ी-फड़ी वि`ताओं के लिए भी एक योजना लेकर आएगी। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बाल किशन ने कहा कि व्यायापारियों के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।

-संवाद ब्यूरो

हरियाणा की योजनाएं बन रही नज़ीर

हरियाणा सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल बनती जा रही हैं। कई योजनाएं ऐसी बन पड़ी हैं कि उनको दूसरे प्रदेश भी लागू कर रहे हैं। वहां के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का हरियाणा दौरा हो रहा है। वे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि योजनाओं को किस प्रकार अमलीजामा पहनाया गया है।

गौरतलब है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शी व्यवस्था और लोगों की जीवन शैली को सहज बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने कई नई पहल की हैं जिनकी देशभर में काफ़ी सराहना हुई है। ऐसी ही योजनाओं में से एक परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) योजना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है।

इसके जरिए परिवारों को प्रत्येक व्यक्तिगत योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों का स्वतः चयन किया जाता है। परिवार आईडी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का आटोमेटिक स्व-चयन किया जाएगा।

हरियाणा की लाल डोरा मुक्त करने की योजना को केंद्र ने पूरे देश में स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया है। कई राज्य अभी भी प्रदेश की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिनों गुजरात का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा की खेल नीति और उत्तराखंड का एक प्रतिनिधिमंडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन करने यहां पहुंचा था।

कार्यकर्ता लोगों को अवगत कराएं: सीएम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा के एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिनके जरिए लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को इन योजनाओं से अवगत कराएं तथा उन्हें इन योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करें।

हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना को उत्तर प्रदेश ने भी अपनाया है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने हरियाणा की इस योजना का अध्ययन किया और अब यूपी सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पीपीपी की तरह परिवार आईडी जारी करेगी। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, रोज़गार या स्वरोज़गार से वंचित परिवारों को चिह्नित किया जाएगा। इसके तहत हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोज़गार तथा स्वरोज़गार के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी सरकार द्वारा शीघ्र ही ऐसे परिवारों की मैपिंग कराई जाएगी, जिनके किसी सदस्य ने कभी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं की।

इसी तरह कई अन्य राज्य भी हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और अपने राज्यों में इन जनहितैषी नीतियों को लागू करने की योजना बना रहे हैं। यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि हरियाणा विभिन्न योजनाओं को सफलता से शुरू करने में बढ़त बनाए हुए है।

- मनोज प्रभाकर

बजट की योजनाओं पर जल्द कार्य करें अधिकारी

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आम बजट में नागरिकों के हितार्थ की गई योजनाओं एवं घोषणाओं को तुरंत प्रभाव से क्रियान्वयन करें ताकि उनका लाभ जल्द से जल्द मिलना आरंभ हो जाए। मुख्यमंत्री ने 15 विभागों की लगभग 67 नई घोषणाओं पर विस्तार से समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध ढंग से ि`यान्वयन करने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यों के क्रियान्वयन में बाधाएं आईं, लेकिन अब हमें तेज़ी से कार्य कर लोगों को लाभान्वित करना है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद व पंचकूला में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाने हैं। इनकी सभी औपचारिकताएं इसी माह पूरी करके अगले माह से कार्य आरंभ कर दिया जाए। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मज़दूरों के बच्चों के लिए क्रैच सेंटर चलाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चार हजार प्ले-वे स्कूलों की प्रक्रिया में भी तेज़ी लाई जाए। हर जिले में पांच एकड़ भूमि से अधिक क्षेत्र में लगाए जाने वाले 'अमृत वन योजना' के तहत सार्वजनिक स्थलों व अमृत सरोवरों के चारों तरफ़ भी ज़्यादा से ज़्यादा छायादार पौधे लगाए जाएं। इसके अलावा अरावली क्षेत्र गुरुग्राम में बनाए जाने वाले सफारी पार्क की प्रक्रिया में भी तेज़ी लाई जाए।

मनोहर लाल ने कहा कि साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए हर जिले में थाने शुरू किए जाएं ताकि यह थाने एडीजीपी मुख्यालय को सीधे अपनी रिपोर्ट अप्रैल माह से भेजना सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा 'सुरक्षा प्रहरी योजना' के तहत 80 साल से अधिक आयु के अकेले रहने वाले बुजुर्गों का हर माह हाल-चाल पूछने के लिए सम्पर्क स्थापित किये जाने का कार्य भी जल्द शुरू किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग सेंटर तुरंत प्रभाव से शुरू किए जाएं। 'चिरायु हरियाणा योजना' के सफल क्रियान्वयन के लिए पोर्टल तैयार किया जाए ताकि उनका रजिस्ट्रेशन कर स्वास्थ्य लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाली चैरिटेबल संस्थाओं का इसमें सहयोग लिया जाए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य चैकअप जल्द हो सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के कार्यों में तेज़ी लाई जाए।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महेन्द्रगढ़ के ढोसी पहाड़, लोहगढ में बाबा बंदा सिंह बहादुर मैमोरियल तथा राखीगढ़ी में जो कार्य चल रहे हैं उन्हें भी तेज़ी से पूरा किया जाए। 'पीएम श्री योजना' के तहत हर ब्लॉक में बनाए जाने वाले स्कूलों में आधारभूत संरचानात्मक ढांचा भी तैयार किया जाए। पशुओं के उपचार के लिए चलाई जाने वाली 70 मोबाइल युनिट भी जल्द शुरू की जाए। ड्रोन खरीदने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

- संवाद ब्यूरो

राज्य में स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले ऐसे किसान, जिसके पास 2 से 5 एकड़ भूमि है, उनको देसी गाय की खरीद पर अधिकतम 25 हजार रुपए की सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगाए जा रहे अंत्योदय उत्थान मेलों के माध्यम से प्रदेश के युवा अब वीटा बूथ व हरहित स्टोर खोल कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

अखिल भारतीय वन खेल-कूद प्रतियोगिता

छत्तीसगढ़ बना चैम्पियन

26वीं अखिल भारतीय वन खेल-कूद प्रतियोगिता का ताऊ देवी लाल स्टेडियम पंचकूला में समापन हुआ। राष्ट्रीय स्तर की इस खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल ट्रॉफी जीत कर छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम रहा, जबकि दूसरा स्थान कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ है।

समापन समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह वन कर्मियों एवं वन अधिकारियों में व्याप्त खेल के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है कि प्रतियोगियों में लगभग 36 खेलों की 273 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया जिसमें कि एकाकी एवं टीम खेल शामिल हैं। वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के प्रयोजन से प्रथम बार अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सन् 1993 में हैदराबाद में किया गया। उन्होंने कहा कि अपने दैनिक कार्यों के लिए वन में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारियों को दुर्गम वन क्षेत्रों में कार्य करना रहता है जिसमें कि वन क्षेत्रों की दैनिक गश्त भी शामिल है इसलिए उनका शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं गतिशील होना आवश्यक है। अपने कार्यों के उचित निष्पादन के लिए वन प्रहरियों के रिफलैक्स त्वरित होने चाहिए ताकि किसी भी खतरे के अंदेशे से बचा जा सके। खेल ऐसा माध्यम है जिससे कि शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है तथा व्यक्ति के रिफलैक्स भी तेज रहते हैं । उन्होंने कहा कि वन कमिर्यों एवं वन अधिकारियों की जीवन शैली में खेल अभिन्न अंग है।

राज्यपाल ने कहा कि वन कर्मी अपने कर्तव्य के लिए लगातार 24 घंटे तथा वर्ष के सारे दिन बड़ी तत्परता से तैयार रहते हैं। उनकी यह प्रकृति एवं वन्य जीवों के प्रति निष्ठा भावना का परिणाम है कि बहुत से वन्य जीव जो कि विलुप्ता की कगार पर थें जिसमें कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ भी शामिल है कि संख्या गत वर्षो में बढ़ रही है। यद्यपि हरियाणा मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है परन्तु यहां पर भी वन कर्मियों ने अपने योगदान से शिवालिक के पहाड़ी क्षेत्रों एवं अरावली क्षेत्र में विद्यमान वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य देश के लिए वेटलिफिटिंग, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, बोक्सिंग, जैवलिन आदि खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देता रहा है।

उन्होंने कहा कि जीवन में धैर्य और अनुशासन से ही व्यक्ति सफल हो पाता है और खेलों में भी धैर्य और अनुशासन ही जीत की पूंजी है। एक अच्छा खिलाड़ी खेल में आई हुई कठिनाईयों से उभरकर जीत का वरण करता है और ऐसे ही जीवन में खेलों जैसी जीवटता रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। खेल के अभ्यास से मनुष्य का चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है ।

खेल में टीम भावना महत्वपूर्ण : ज्ञानचंद गुप्ता

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि खेल मनुष्य में आपसी समझ को बढ़ावा देते है क्योंकि कोई भी खेल अकेले नहीं खेला जा सकता। टीम के साथ खेलकर हमें सहयोग से काम करने की आदत पड़ती है। मिलकर खेलने में व्यक्तिगत हार-जीत नहीं रहती। हार का दुःख तथा जीत की खुशी साथी खिलाडियों में बंट जाती है। उन्होंने कहा कि खेल में जीत के लिए आवश्यक है कि खिलाड़ी व्यक्तिगत यश के लिए न खेलें। वह अन्य खिलाडियों के साथ सहयोग से खेलें। इस प्रकार खेलों से टीम भावना तथा सहकारिता की भावना से काम करने की शिक्षा स्वयमेव मिलती रहती है।

खेल सबके लिए जरूरी : कंवरपाल

हरियाणा के वन एवं वन्य जीव मंत्री कंवरपाल ने कहा कि यह अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता लघु भारत की एक मनोरम झांकी है। यहां हार-जीत का महत्व नहीं है बल्कि खेल भावना का महत्व है। उन्होंने कहा कि स्फूर्तिमय शरीर ही मन को स्वस्थ बनाता है। खेलकूद मानव मन को प्रसन्न और उत्साहित बनाए रखते है। खेलों से नियम पालन के स्वभाव का विकास होता है और मन एकाग्र होता है। खेल मे भाग लेने से खिलाड़ियों में सहिष्णुता, धैर्य और साहस का विकास होता है तथा सामूहिक सदभाव और भाईचारे की भावना बढ़ती है। खेलकूद अप्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होते हैं ये जीवन संघर्ष का मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करते है। खेलकूद से एकाग्रता का गुण आता है जिससे आध्यात्मिक साधना में मदद मिलती है ।

- संवाद ब्यूरो

बिजली का विकल्प बनती सोलर योजना

विद्युत संकट अब संकट नहीं रह गया है। एक ओर जहां राज्य सरकार लगभग सभी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का प्रयास कर ही है तो दूसरी ओर सोलर एनर्जी पर भी प्रोत्साहन दे रही है। किसान अपने खेतों में पम्प चलाने के लिए इस ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगे हैं। आम परिवार भी इस योजना के साथ जुड़कर लाभ लेने लगे हैं। सोलर इन्वर्टर की संख्या में इजाफ़े से वायु-प्रदूषण में भी कमी आई है।

हरियाणा सोलर इन्वर्टर चार्जर योजना कारबर साबित हो रही है। योजना की मुख्य विशेषताओं के तहत घरों में पहले से लगे हुए इनवर्टर और बैटरियों को चार्ज करने के लिए 300 वाट और 500 वाट की क्षमता वाले सोलर पैनल चार्ज कंट्रोलर पर 40 प्रतिशत सब्सिडी सरकार प्रदान कर रही है। बाजार की स्थिति को देखा जाये तो इसमें 300 वाट के सोलर पैनल की कुल कीमत लगभग 15,000 रुपए है जिस पर सरकार द्वारा 6,000 रुपए तथा 500 वाट के सोलर पैनल की कुल कीमत लगभग 22,000 रुपए है जिस पर 10,000 रुपए की सब्सिडी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है ।

मनोहर ज्योति योजना में दो वॉट की एल.ई.डी बल्ब, एक 9 वाट एल.इ.डी टयूब लाईट, एसी/ डीसी सिलिंग पंखा, माबाईल चार्जर होता है। जो 12 वॉट- 125 ए.एच. बैटरी व 150 वाट के सोलर पैनल के साथ सोलर लगभग 6 से 8 घंटे प्रतिदिन काम में लाया जा सकता है। जिस पर 15000 रुपए भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। आवेदक को लगभग 7500 रुपए में उपलब्ध करवाया जाता है।

इसी प्रकार सोलर स्ट्रीट लाईट में सड़कों पर उपयोग करने के लिए 12 वॉट एलईडी लाईट होती है और 12 वोल्ट की लीथियम फैरो फास्फेट बैटरी से कार्य करता है। इस बैटरी को 75 वॉट के सोलर पैनल द्वारा दिन में चार्ज किया जाता है। यह उपकरण अंधेरा होने पर स्वयं चलने लगता है। इसकी कीमत लगभग 19057 रुपए है जिस पर केंद्र सरकार द्वारा 5117 रुपए व राज्य सरकार द्वारा 4000 रुपए अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।

सरकार की योजना के तहत सौर फोटोवोल्टेक पम्पिंग सिस्टम का दिन के समय सौर उर्जा से बिजली उत्पादन करके सौर फोटोवोल्टेक पम्पिंग सिस्टम से सिंचाई की जाती है। इसमें 3 एचपी.5 एचपी. व 10 एच.पी.डी.सी/ एसी सबमर्सीबल सोलर टयूबवैल पर 75 प्रतिशत हरियाणा व भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।

योजना के तहत राज्य के नागरिक ही हरियाणा के सरल पोर्टल पर अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। आवेदन करने वाले व्यक्ति का बैंक खाता होना अनिवार्य है क्योंकि सब्सिडी की राशि सीधे खाते में डाली जायेगी।

योजना 2020 में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जगह का फोटो जहां पैनल लगाया जाना है। बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो प्रमुख हैं।

-संवाद ब्यूरो

केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण उर्जा मंत्रालय के तहत बायोगैस संयंत्र स्थापित करने पर अनुदान दिया जा रहा है। एक से छह घन मीटर क्षमता के बायोगैस प्लांट के इच्छुक नागरिक पोर्टल biogas.mnre.gov.in पर आवेदन करें।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 151 मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 10-10 लाख रुपए सावधिक बीमे की पॉलिसी प्रति प्रदान की है। इन पत्रकारों से बीमा के प्रीमियम का एक भी पैसा उनसे नहीं लिया गया है।

संस्कृति का प्राण है लोक साहित्य

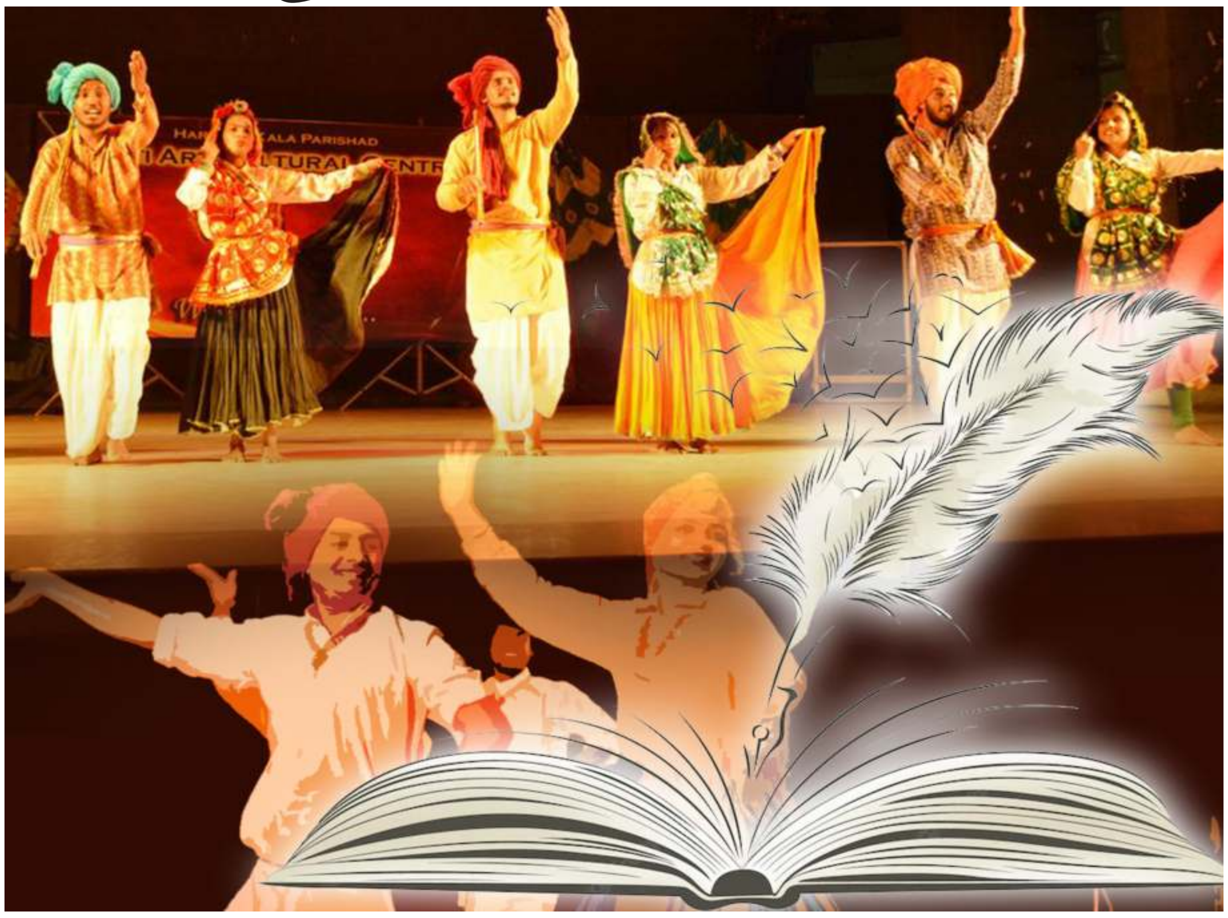

केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने माधव कौशिक

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने साहित्यकार, लेखक एवं चिंतक माधव कौशिक को केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त होने पर शुभकामनाएं दीं। श्री कौशिक मूलतः भिवानी के रहने वाले हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माधव कौशिक हरियाणा की मिट्टी से जुड़े साहित्यकार हैं और वे हरियाणा की संस्कृति के विस्तारीकरण में ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। माधव कौशिक ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने उन्हें आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार से जो सम्मान दिया है वह उसके लिए सदैव आभारी रहेंगे।

कौशिक ने कहा कि केंद्रीय साहित्य अकादमी व हरियाणा साहित्य अकादमी मिलकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मेलनों का आयोजन करेंगे ताकि साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े लेखकों को बेहतर मंच उपलब्ध हो सके।

जनमानस की भावनाओं को प्रभावित करने वाली मुंहबोली शाब्दिक रचनाएं लोक साहित्य की कृति मानी जाती हैं। हरियाणा के साहित्यिक इतिहास में ऐसी रचनाओं का अकूत भंडार है। स्थानीय बोली के अनेक विद्वानों ने अपने-अपने प्रारूप से यहां के इतिहास को समृद्ध किया है। रचनाकारों की फेहरिस्त और उनका आलोक इतना विस्तृत है कि इस लेख में उन पर चर्चा करना सूर्य को रोशनी दिखाने वाली बात कही जाएगी।

पंडित लख्मीचंद को यहां का सूर्यकवि माना जाता है। दादा लख्मी के अलावा अनेक ऐसे प्रख्यात एवं मूर्धन्य कवि हुए जिनकी रचनाएं कालजयी बन गई। सांग लोक साहित्य की प्राचीन विद्या रही है। सांगों के जरिए तत्कालीन कवियों ने समाज की विसंगतियों पर कुठाराघात किया तथा समाज के उत्थान के लिए खूब काम किया। कथाओं के जरिए समस्याओं व बुराइयों को रेखांकित करते हुए वर्तमान को संवारने का निरंतर प्रयास किया। इन प्रयासों में वे कामयाब भी रहे। कहने का तात्पर्य लोक को आलोकित किया।

समय बीतता गया और सांगों की लोकप्रियता कम होती चली गई। उल्लेखनीय है कि उस दौर में जब ग्रामीण विकास की बात होती थी तो उसके लिए चंदा जुटाने का कार्य सांगों के जरिए ही होता था। स्थानीय लोगों द्वारा चंदा दिया जाता था तथा सांगी द्वारा उनके 'चमोले' की मंच से घोषणा की जाती थी। धन एकत्र करने की इस परंपरा में अक्सर स्थानीय लोग होड़ में एक दूसरे से बढ़-चढ़कर दान देते थे।

आर्थिक पक्ष के अलावा सांगों की कथा, नृत्य एवं भाव विह्वल कर देने वाली प्रस्तुति की चर्चा की जाए तो वह बेजोड़ है। लोक कवियों की रचनाएं अनेक रसों से सराबोर होती थी। विस्मय, श्रृंगार, करूणा, वीरता व अन्य भावों से ओतप्रोत रागणियां जन मानस के जहन में सीधे उतर जाया करती थी।

लोकगीत अति प्राचीन विधा है जिसके बिना लोक साहित्य की कल्पना करना बेमानी है। इन्हीं लोक गीतों से क्षेत्र की संस्कृति समृद्ध हुई है। स्थानीय संस्कृति के विभिन्न रंगों से सजा लोक साहित्य विभिन्न तीज त्यौहारों पर आज भी दर्शन करा रहा है। विभिन्न पर्व, मेले, शादी- ब्याह के अवसर, बच्चे के जन्म पर, तालाब, पनघट, खानपान, चिकित्सा, शिक्षा, खेत-खलिहान, ऋतु, विशेषकर बरसात के मौसम पर, नदी, बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदा, रोग, प्राकृतिक सौंदर्य, चांद, सूरज आदि अनेक पहलूओं पर लोकगीत गढ़े और गाए गए हैं। लोक को वैचारिक मंथन पर विवश करने वाला इन गीतों का दार्शनिक पहलू सच में विस्मयकारी है।

मानवीय रिश्तों के पोषण पर अनेक गीतों का सृजन हुआ है। देवर-भाभी के रिश्तों को इतना पावन बताया गया है कि क्या मजाल किसी के मन में कुछ नकारात्मक सोच जन्म ले। कथाओं के जरिए जिक्र उन मौकों का भी हुआ है जब गांव-गुहांड की कन्या को भी बहन का दर्जा दिया जाता था और उसे मान-सम्मान के रूप में टका दिया जाता था। उस दौर के कवियों ने रिश्तों की बनावट पर इतना कुछ गढ़ा और बुना है कि उसके तरन्नुम से पूरा समाज प्रेम एवं सौहार्दपूर्ण महौल में प्रसन्न रहता था। सामाजिक बुराइयों के पनपने की गुंजाइश नहीं रहती थी। परस्पर सहयोग एवं एकजुटता की स्पर्धा थी।

खास बात यह है कि उस समय उन कवियों को सुना जाता था। सांगों के बाद दौर आया रागनी कम्पीटीशन का। वह दौर भी समय के साथ विस्मृत हो गया। आज वे विद्याएं तो लगभग लोप हो गई हैं लेकिन उस दौर का रचित लोक साहित्य किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान है। राज्य या क्षेत्रिय स्तर पर स्थित पुस्तकालयों में वह साहित्य मौजूद तो है लेकिन धूल फांकने पर विवश है। मोबाइल फोन संस्कृति लोक साहित्य एवं संस्कृति पर हावी हो गई है। लोगों ने किताबों से दूरी बना ली है। साहित्य और लोक साहित्य विषय आज की युवा पीढ़ी से दूर हो चला है। बहुत से युवा तो यही नहीं जानते कि साहित्य होता क्या है?

साहित्य अनेक रूपों में विद्यमान है। दर्शन, समाज, राजनीति, धर्म, अर्थ, विधि व अनेक संकायों में इसको पढ़ा व आत्मसात किया जा सकता है। धार्मिक गुरुओं, महान कवियों एवं विद्वानों ने जगत कल्याण के लिए अनेक कालजयी रचनाएं दी हैं। ऐसी रचनाएं जो उलझी गुत्थियों को खोल दें और मानव जीवन को सहज व सरल कर दें। कहते हैं एक लाठी वह काम नहीं कर सकती जो एक शब्द या वाक्य कर सकता है। इसीलिए शब्द को ब्रह्मा की भी संज्ञा दी गई है। उपनिषदों में जीवन का सार दिया गया है।

साहित्य जीवन को संवारता है, लयबद्ध करता है, सलीके से जीना सिखाता है। तो फिर क्यों आज हम साहित्य से विमुख होते जा रहे हैं? वर्तमान दौर में साहित्य से जुड़े कर्ता-धर्ताओं की जिम्मेवारी बनती है कि डिजिटल संस्कृति की चुनौतियों का सामना करते हुए कुछ इस तरह की सार्थक एवं निष्पक्ष पहल की जाएं कि आम जनमानस साहित्य के सानिध्य में कुछ समय बीताने लगे।

-मनोज प्रभाकर

'पगडंडियों के सफर' में 'माटी की खुशबू'

साहित्य अकादमी में तीन पुस्तकों का विमोचन

हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. चन्द्र त्रिखा ने पंचकूला स्थित अकादमी भवन में साहित्यकार व छायाकार डॉ. ओम प्रकाश कादयान की नव प्रकाशित पुस्तक 'पगडण्डियों का सफर' तथा लेखक, कवयित्री डॉ. सुमन कादयान की दो पुस्तकों 'हरियाणवी मुहावरे व लोकोक्तियाँ', 'माटी की खुशबू' (हरियाणवी कविताओं) का विमोचन किया।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक डॉ. प्रदीप राठौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर सम्पादक विजेन्द्र कुमार, हरियाणा साहित्य अकादमी की अधिकारी मनीषा नांदल, प्रसिद्ध चित्रकार भीम सिंह आदि मौजूद थे।

डॉ. चन्द्र त्रिखा ने कहा कि यात्राएं हमें व्यवहारिक ज्ञान देती हैं, हमें अनुभवी व साहसी बनाती हैं। घुमक्कड़ को सीधे तौर पर समाज व प्रकृति से जोड़ने का काम करती हैं। साहित्यकार डॉ. ओम प्रकाश कादयान का यात्रा वृतान्त संग्रह 'पगडंडियों का सफर' पाठकों को घर बैठे देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, हिमालय की दुर्गम, खूबसूरत घाटियों की यात्राएं करवाएगा। मरुस्थल की खूबसूरती तथा समुन्द्र की विशालता का अहसास करवाएगा।

डॉ. चन्द्र त्रिखा ने कहा कि डॉ. सुमन कादयान की पुस्तक 'माटी की खुशबू' हरियाणवी लोक भाषा को समृद्ध करने में सहायक होगा तो 'हरियाणवी मुहावरे व लोकोक्तियां' पुस्तक हरियाणवी लोकसाहित्य से परिचित करवाएगी। डॉ. त्रिखा ने कहा कि अधिक लेखन महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कालजयी, प्रभावशाली व उपयोगी लेखन जरूरी है। इस दृष्टि से ये किताबें अच्छे साहित्य की पूर्ति करती हैं।

डॉ. प्रदीप राठौर ने कहा कि यात्रा साहित्य अन्य विद्याओं की अपेक्षा कम लिखा जा रहा है, ऐसे में 'पगडंडियों का सफर' पुस्तक का महत्व और भी बढ़ जाता है। 'हरियाणा के मुहावरे व लोकोक्तियां' हमारे लोक का आइना है। डॉ. ओमप्रकाश कादयान व डॉ. सुमन सम्मान के पात्र हैं। डॉ. सुमन ने लोक साहित्य के महत्व पर प्रकाश डाला तो डॉ. ओमप्रकाश कादयान ने यात्राओं से सम्बंधित किस्से साझा किए।

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com